पंजाब विश्वविद्यालय

बनाम

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

(2007 का सिविल अपील संख्या 400 आदि)

09 जुलाई, 2014

[न्यायाधिपति चंद्रमौली के. आर. प्रसाद और न्यायाधिपति पिनाकी चंद्र घोस]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: धारा 2 (1) (घ) (i) और (ii)-- "उपभोक्ता" - "व्यावसायिक उद्देश्य" - यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीई) द्वारा शुरू की गई "संस्थागत निवेशक विशेष निधि इकाई योजना, 1998" (आईआईएसएफयूएस-98) में निवेश करने वाले विश्वविद्यालय - राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विश्वविद्यालयों द्वारा शिकायतें कि परिपक्वता आगे बढ़ती है निर्धारित की गई रखरखाव/योग्यता से बहुत कम थे - माना गया: "वाणिज्यिक उद्देश्य" शब्द की व्याख्या प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए की जानी चाहिए - 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द एक ऐसे उपक्रम को कवर करेंगे जिसका उद्देश्य है उपक्रमों से लाभ कमाना - तत्काल मामले में, शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए यूटीआई की सेवाओं का लाभ उठाया गया था, और शिकायतकर्ताओं को लाभ के रूप में कोई लाभ नहीं मिला था - 'वाणिज्य' शब्द की परिभाषा के मद्देनजर, नहीं के तहत परिस्थितियों के अनुसार, अपीलकर्ताओं को किसी भी 'व्यावसायिक' गतिविधि में शामिल कहा जा सकता है - इस प्रकार शिकायतकर्ता-विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में परिभाषित "उपभोक्ता" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और शिकायतें पहले सुनवाई योग्य हैं राष्ट्रीय आयोग - हालाँकि, योग्यता के आधार पर, शिकायतकर्ताओं के पास कोई

मामला नहीं है - यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। 'प्रस्ताव की शर्तें' पर परिपक्वता राशि निर्भर करेगी। एनए वी और यह गारंटी दी गई थी कि यह प्रति यूनिट 10 रुपये के सममूल्य से कम नहीं होगा - सभी निवेश बाजार जोखिम और उतार-चढ़ाव के अधीन हैं और निवेशकों को किसी भी योजना में किसी भी राशि का निवेश करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी - सिर्फ इसलिए कि परिपक्वता राशि उनकी अपेक्षाओं से कम है, वे इसके लिए सेवा प्रदाता को अदालत में नहीं खींच सकते - राष्ट्रीय आयोग ने गुण-दोष के आधार पर शिकायतकर्ताओं के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 (यूके) – धारा 20 (6)।

अपीलकर्ता सी.ए. 2007 की संख्या 400, अर्थात्, पंजाब विश्वविद्यालय ने, प्रतिवादी-यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई "संस्थागत निवेशक विशेष निधि इकाई योजना, 1998" (आईआईएसएफयूएस-98) में निवेश किया, इस विशिष्ट समझ के साथ कि लाभांश प्राप्य है योजना अवधि के दौरान पुनर्निवेश किया जाएगा और इसे न्यूनतम 13.5% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। यह निवेश "फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च" फंड से किया गया था। यूटीआई ने 1,90,00,000 इकाइयों और 45,00,000 इकाइयों के लिए क्रमशः 19 करोड़ रुपये और 4.5 करोड़ रुपये के दो आईआईएसएफयूएस-98 प्रमाणपत्र जारी किए, जिसमें प्रत्येक इकाई का अंकित मूल्य 101 रुपये था- जब परिपक्वता राशि के चेक प्राप्त हुए थे अपीलकर्ता ने इसे परिपक्वता आय से काफी कम पाया। अपीलकर्ता विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक शिकायत दायर की जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी ने आश्वासन दिया था कि लाभांश आय को नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर आगे की इकाइयों में पुनर्निवेश किया जाएगा और उन इकाइयों पर विश्वविद्यालय को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें न्यूनतम रिटर्न मिलेगा। 13.5% प्रति वर्ष की दर से और इसे बराबर यानी 101 रुपये की दर से पुनर्खरीद किया जाएगा-राष्ट्रीय आयोग ने

प्रतिवादी-संस्थान द्वारा सेवा में कमी के लिए अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय की शिकायत को विचारणीय माना, लेकिन इसे खारिज कर दिया। पंजाब विश्वविद्यालय के साथ-साथ यूटीआई ने भी अपील दायर की। दूसरी अपील पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा समान परिस्थितियों में दायर की गई थी।

तत्काल अपील में, यूटीआई के लिए यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(डी) के तहत परिभाषित "उपभोक्ता" शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं और प्रतिवादी-यूटीआई प्रदान नहीं कर रहा है। अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के अनुसार परिभाषित कोई भी "सेवाएँ"। यह प्रस्तुत किया गया था कि यूटीआई की योजनाओं में भाग लेने की सेवाएँ व्यावसायिक उद्देश्य के लिए थीं, यदि इसका लाभ किसी व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नहीं लिया गया था। स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करना।

न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थे: "क्या शिकायतकर्ता-विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में निर्धारित "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे में आते हैं और उनके द्वारा किराए पर ली गई "सेवाएँ" किसी भी "व्यावसायिक उद्देश्य" के लिए नहीं हैं; और "क्या प्रस्ताव के संदर्भ में, सेवाओं में कोई कमी है।"

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(डी) के खंड (i) और (ii) की व्याख्या, सामंजस्यपूर्ण ढंग से और उसी के आलोक में की जानी चाहिए, धारा 2(1)(डी)(ii) के बाद स्पष्टीकरण अधिनियम स्पष्ट प्रकृति का होगा और तत्काल मामले पर लागू होगा और जैसा कि लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, "व्यावसायिक उद्देश्य" शब्द की व्याख्या प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने आगे कहा कि

संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया स्पष्टीकरण प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण है और चूंकि अधिनियम का मतलब हमेशा एक ही होता है, इसलिए संशोधन सभी लंबित कार्यवाहियों पर भी लागू होगा। [पैरा 19-20] [288-एफ; 290-ई-एफ]

*लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पी.एस.जी. इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट 1995 (3) एससीआर 174 = 1995 (3) एससीसी 583; लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के गुप्ता 1993 (3) पूरक एससीआर 615 =1994 (1) एससीसी243 - पर भरोसा किया।

1.2. 'व्यावसायिक प्रयोजन' शब्द में एक उपक्रम शामिल होगा जिसका उद्देश्य उपक्रम से लाभ कमाना है। तत्काल मामले में शिकायतकर्ता द्वारा अपने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए यूटीआई की सेवाओं का लाभ उठाया गया था, इसलिए, ऐसा निवेश किया गया था, और शिकायतकर्ता को अपनी बैलेंस-शीट में सुधार करने के लिए लाभ के रूप में कोई लाभ नहीं मिलना था। 'वाणिज्य' शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिस्थिति में अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी 'व्यावसायिक' गतिविधि में शामिल होना ताकि इसे अधिनियम में निहित 'उपभोक्ता' की परिभाषा से बाहर रखा जा सके। तत्काल विवाद में विश्वविद्यालयों का इरादा मुनाफाखोरी का नहीं है और यह परोपकारी हित के लिए है और ऐसा कोई नहीं है। इरादा चाहे जो भी हो कि निवेश किसी व्यावसायिक उद्देश्य या लाभ के लिए किया गया है और इसलिए,शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय धारा में परिभाषित "उपभोक्ता" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम के 2(1)(डी) और शिकायतें राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विचारणीय हैं। [पैरा 21) [291-एफ-एच; 292-ए-बी]

स्ट्राउड के न्यायिक विवेचन - का उल्लेख किया गया है।

1.3. गुण-दोष के आधार पर, शिकायतकर्ताओं के पास कोई मामला नहीं है। 'प्रस्ताव की शर्तों' में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि परिपक्वता राशि

एनएवी पर निर्भर करेगी और यह गारंटी दी गई थी कि यह प्रति यूनिट 10 रुपये के सममूल्य से कम नहीं होगी। सभी निवेश बाजार जोखिम और उतार-चढ़ाव के अधीन हैं और निवेशक को किसी भी योजना में कोई भी राशि निवेश करते समय उचित सावधानी बरतनी होती है; सिर्फ इसलिए कि परिपक्वता राशि निवेशकों की अपेक्षा से कम है, वे इसके लिए सेवा प्रदाता को अदालत में नहीं खींच सकते। [पैरा 22) [293-ई-जी]

4. राष्ट्रीय आयोग ने सही ढंग से माना कि शिकायतकर्ता-विश्वविद्यालय "उपभोक्ता" के दायरे में आएंगे और योग्यता के आधार पर उनके शिकायतकर्ताओं को खारिज कर दिया। [पैरा 23) [293-एच; 294-ए]

मॉर्गन स्टेनली म्यूचुअल फंड बनाम कीर्तिक दास 1994 (1) पूरक एससीआर 136 = 1994 (4) एसईसी 225 - उद्धृत।

वाद कानून संदर्भ

1995 (3) एससीआर 174	निर्भर	पैरा 6
1994(1)पूरक एससीआर 136	हवाला दिया	पैरा 15
1993 (3) पूरक एससीआर 615	निर्भर	पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 400/2007

2004 की मूल याचिका संख्या 97 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.2006 से।

साथ

सीए 2008 की संख्या 503 और 2009 की 4664

उपस्थित पक्षों के लिए अमरेंद्र शरण, विभव तिवारी, रवि प्रकाश मेहरोत्रा भार्गव वी.देसाई, श्रेयस मेहरोत्रा, अन्नम डी.एन. राव अन्नम वेंकटेश, सुदीप्तो सरकार, नीलम जैन, वैशाली आर. शिवाजी एम. जाधव।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

पिनाकी चंद्र घोष, जे.:

1. 2008 की सिविल अपील संख्या 503 दाखिल करने में देरी माफ की जाती है।

2. 2007 की सिविल अपील संख्या 400 पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दायर की गई है, जो आम जनता को शिक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के तहत गठित एक वैधानिक/स्वायत्त निकाय है। 2008 की सिविल अपील संख्या 503 क्रॉस अपील दायर की गई है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। उपरोक्त दोनों अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद के 17 अक्टूबर, 2006 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध उत्पन्न हुई हैं। 2004 की मूल याचिका संख्या 97 में निवारण आयोग (इसके बाद इसे "राष्ट्रीय आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (इसके बाद इसे "यूटीआई" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ शिकायतकर्ता होने के नाते पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दायर किया गया था। यूटीआई द्वारा दायर 2009 की सिविल अपील संख्या 4664 राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2005 की मूल याचिका संख्या 51 में पारित 17 अप्रैल 2009 के आदेश के खिलाफ है, जिसे शिकायतकर्ता पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विपरीत पक्ष यूटीआई के खिलाफ दायर किया है।

3. चूंकि दोनों मामलों में दायर उपभोक्ता शिकायत एक ही योजना "संस्थागत निवेशक विशेष निधि इकाई योजना, 1998" (इसके बाद आईआईएसएफयूएस-98 के रूप में संदर्भित) से संबंधित है, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय (मूल याचिका में

शिकायतकर्ता) 2004 की संख्या 97) और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (2005 की मूल याचिका संख्या 51 में शिकायतकर्ता) ने निवेश किया और राष्ट्रीय आयोग ने आदेश पारित करते हुए 2005 की मूल याचिका संख्या 51 में 2004 की मूल याचिका संख्या 97 में दिए गए अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय के माध्यम से उनका निपटारा किया जा रहा है।

4. इन अपीलों में विवाद को समझने के लिए, हम संक्षेप में तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे, जो संक्षिप्तता के लिए 2007 की सिविल अपील संख्या 400 से निकाले गए तथ्यों तक सीमित है और निम्नानुसार बताया गया है:

4.1. पंजाब विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज के लिए हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करता है और इस उद्देश्य के लिए इसे अपने कर्मचारियों को वेतन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी अनुदान प्राप्त होता है। अंशदायी भविष्य निधि योजना-अपने कर्मचारियों के लिए और इसके फंड का रखरखाव और प्रबंधन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, वर्ष 1993 में, पंजाब विश्वविद्यालय ने "संस्थागत निवेशक विशेष निधि इकाई योजना-93" (इसके बाद " आईआईएसएफयूएस-93 के रूप में संदर्भित) में 9.6 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया। यूटीआई की जो एक ओपन एंडेड योजना थी।

4.2. राशि को लाभांश के पुनर्निवेश विकल्प के साथ निवेश किया गया था और 31 मार्च 1998 को यूटीआई द्वारा योजना समाप्त करने पर उक्त राशि 19.78 करोड़ रुपये हो गई। इस योजना ने मूल पूंजी की सुरक्षा की गारंटी दी और 16% प्रतिवर्ष देय रिटर्न का आश्वासन दिया। अर्धवार्षिक। आईआईएसएफयूएस-93 योजना को यूटीआई द्वारा 31

मार्च 1998 से एकतरफा समाप्त कर दिया गया और परिपक्वता राशि 19,78,26,299.44 रुपये हो गई।

4.3. इसके बाद, वर्ष 1998 में, यूटीआई द्वारा एक और योजना यानी आईआईएसएफयूएस -98 शुरू की गई और पंजाब विश्वविद्यालय ने 19 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया, जो उसे आईआईएसएफयूएस -93 की परिपक्वता पर एक विशिष्ट समझ के साथ प्राप्त हुई थी कि योजना के दौरान प्राप्त लाभांश अवधि का पुनर्निवेश किया जाएगा और इसे 13.5% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

4.4. 19 करोड़ रुपये को आईआईएसएफयूएस -93 से आईआईएसएफयूएस -98 में बदलने के मद्देनजर, विश्वविद्यालय ने 4.5 करोड़ रुपये का निवेश भी किया। यह निवेश "फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च" फंड से किया गया था। मुंबई में यूटीआई के प्रधान कार्यालय ने 1,90,00,000 इकाइयों और 45,00,000 इकाइयों के लिए क्रमशः 19 करोड़ रुपये और 4.5 करोड़ रुपये मूल्य के दो आईआईएसएफयूएस-98 प्रमाणपत्र जारी किए, जिनमें प्रत्येक इकाई का अंकित मूल्य 10/- रुपये था। इस मामले में विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या विश्वविद्यालय पुनर्निवेशित राशि पर 13.5% की दर से ब्याज पाने का हकदार है, यानी लाभांश जो यूटीआई के साथ पुनर्निवेश किया जाता है।

4.5. 4 जून 2003 को, यूटीआई ने परिपक्वता राशि 30,45,23,910.23 रुपये और 7,13,81,520 रुपये के चेक यूटीआई बैंक लिमिटेड को भेजे और निवेश के खिलाफ परिपक्वता भुगतान का विवरण भी दिया। यूटीआई से 30,45,23,910.23 रुपये का चेक प्राप्त करने पर, जो कि 19 करोड़ रुपये की परिपक्वता राशि थी, अपीलकर्ता विश्वविद्यालय आश्चर्यचकित और हैरान था क्योंकि आईआईएसएफयूएस-98 की "प्रस्ताव

की शर्तों" के अनुसार, परिपक्वता आय होगी। रु.48,76,88,935.12/- जो प्राप्त राशि से अधिक है। विश्वविद्यालय ने ब्याज सहित रु.18,31,65,024.89 और रु.4,21,93,558/- के घाटे के भुगतान के लिए यूटीआई को कानूनी नोटिस भेजा। 10 नवंबर 2004 को, विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष 2004 की मूल याचिका संख्या 97 के रूप में एक शिकायत दर्ज की। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय का तर्क यह था कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि लाभांश आय को नेट एसेट वैल्यू (इसके बाद "एनएवी" के रूप में संदर्भित) पर आगे की इकाइयों में पुनर्निवेश किया जाएगा और उन इकाइयों पर भी, किसी भी मामले में, वे आश्वासन दिया गया था कि उन्हें प्रति वर्ष 13.5% की दर से न्यूनतम रिटर्न मिलेगा और इसे बराबर यानी 10/- रुपये की दर पर पुनर्खरीद किया जाएगा। उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा दायर उक्त शिकायत पर प्रतिक्रिया दर्ज की।

4.6. राष्ट्रीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 द्वारा अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा दायर उक्त शिकायत को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया। हालाँकि, आयोग ने माना कि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय की शिकायत प्रतिवादी-संस्थान द्वारा सेवाओं की कमी के लिए अधिनियम के तहत विचारणीय है। इसलिए, अपीलकर्ता विश्वविद्यालय हमारे सामने राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रहा है और प्रतिवादी-संस्था है। हमारे समक्ष अपनी क्रॉस-अपील में राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना।

5. अपीलकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय का मामला यह है कि यूटीआई 13.5% प्रति वर्ष रिटर्न के आश्वासन का सम्मान करने में विफल रहा और वे अनुबंध का उल्लंघन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इक्विटी बाजारों में 20% से अधिक निवेश किया था जिसके कारण एनएवी गिर गई और यह सेवाओं की कमी के समान है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता कथित गैर-

निष्पादित परिसंपत्तियों के विवरण का खुलासा करने में विफल रहे और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का खुलासा करने में भी विफल रहे और उन्हें समाप्त कर दिया गया। इलाज करना । यह भी प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय आयोग ने प्रस्ताव दस्तावेज पर विचार करने में गलती की, जो कि पार्टियों के लिए बाध्यकारी नहीं था, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि यूटीआई ने उन्हें प्रस्ताव दस्तावेज नहीं दिया था और उन्हें केवल 9 मार्च, 1998 का एक पत्र दिया गया था। यूटीआई के कार्यकारी निदेशक द्वारा संबोधित, प्रस्ताव की शर्तें और रूपांतरण आवेदन लेकिन प्रस्ताव दस्तावेज़ नहीं। अंतिम रूप से यह तर्क दिया गया है कि विवादित आदेश इस तथ्य के मद्देनजर गलत है कि प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार अपीलकर्ता को पार्टियों पर बाध्यकारी हुए बिना प्रस्ताव दस्तावेज़ को पढ़ने की आवश्यकता थी और विकास आरक्षित निधि से संबंधित शर्तें सम्मानित नहीं किया गया।

6. उपरोक्त के अलावा, 2005 की मूल याचिका संख्या 51 में शिकायतकर्ता पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने 2009 की सिविल अपील संख्या 4664 में प्रतिवादी होने के नाते अपनी ओर से उपस्थित विद्वान वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा किया गया निवेश आईआईएसएफयूएस-98 "वाणिज्य" शब्द के अर्थ के अनुसार "वाणिज्यिक" शब्द के अंतर्गत नहीं आ सकता है जैसा कि राष्ट्रीय आयोग ने अपने फैसले में माना है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पी.एस.जी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट१ में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

7. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने आगे कहा कि राष्ट्रीय आयोग के विशिष्ट निष्कर्षों के आलोक में कि "शिकायतकर्ता को लाभ के रूप में कोई लाभ नहीं मिलना था, इसकी बैलेंस-शीट में सुधार करना", इसका कोई सवाल ही नहीं था। विश्वविद्यालय का कोई लाभ कमाना और भले ही विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को

वैधानिक बकाया का भुगतान करने के बाद भी कोई लाभ कमा रहा हो, इसे व्यावसायिक उद्देश्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने यूटीआई द्वारा किए गए वादे के आधार पर पैसा निवेश किया था कि विश्वविद्यालय को भुगतान किया जाएगा। आई आईएसएफयूएस-98 में किए गए निवेश के लिए 13.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज इस कारण से कि यह योजना केवल उन संस्थानों के लिए खुली थी, यूटीआई अपने द्वारा शुरू की गई योजना के लिए प्रतिफल ले रहा था।

8. अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जिन निवेशकों ने यूटीआई योजना में अपना पैसा जमा किया है, वे उपभोक्ता हैं और यूटीआई द्वारा किए गए वादे के उल्लंघन की स्थिति में यह खुला रहेगा। उन्हें सेवा की "कमी" के लिए उपभोक्ता मंचों से संपर्क करना होगा, और यूटीआई यह दलील नहीं दे सकता है कि निवेश लाभ के लिए किया गया था न कि आजीविका कमाने के लिए। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वकील ने एक अंतर प्रस्तुत करते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं यह बनाना होगा कि सामान का आगे उपयोग कैसे किया जाता है;·केवल इसलिए कि यूटीआई के निमंत्रण पर संस्थानों ने आईआईएसएफयूएस-98 में पैसा निवेश किया था, उन्हें केवल इसलिए वाणिज्यिक लोग नहीं कहा जा सकता क्योंकि निवेश कमाई के उद्देश्य से किया गया है लाभ, और यदि ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो जो संस्थान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को आगे बढ़ाने के लिए ब्याज अर्जित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के पास पैसा जमा करते हैं, वे अधिनियम के तहत वादे के उल्लंघन के लिए अपने मामलों में मुकदमा चलाने से वंचित हो जाएंगे। .

9: दूसरी ओर यूटीआई की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(1)(डी) और प्रतिवादी के तहत परिभाषित टेरी "उपभोक्ता" के अंतर्गत नहीं आते हैं। -यूटीआई अधिनियम की धारा 2 (1}(ओ) के तहत परिभाषित कोई भी "सेवाएं" प्रदान नहीं कर

रहा है और इसलिए शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। हम धारा 2(1)(डी) को दोबारा प्रस्तुत करेंगे। तत्काल संदर्भ के लिए अधिनियम का:

(डी) 'उपभोक्ता' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो,-

(i) किसी भी सामान को ऐसे प्रतिफल के लिए खरीदता है जिसका भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के तहत और उस व्यक्ति के अलावा किसी भी सामान का उपयोगकर्ता शामिल है जो ऐसे सामान को भुगतान या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए प्रतिफल के लिए खरीदता है। या आंशिक रूप से वादा किया गया है, या आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी के साथ किया जाता है, लेकिन

इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसा सामान प्राप्त करता है; या

(ii) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए, या आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें सेवाओं को किराए पर लेने या लेने वाले व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल होता है। प्रतिफल के लिए भुगतान किया गया या वादा किया गया, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया और आंशिक रूप से वादा किया गया, या आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लेखित व्यक्ति के अनुमोदन से लिया जाता है, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "व्यावसायिक प्रयोजन" में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के प्रयोजनों के लिए ली गई सेवाओं का उपयोग शामिल नहीं है।

10. यूटीआई की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि ऊपर उद्धृत "उपभोक्ता" की परिभाषा से, यह स्पष्ट है कि "उपभोक्ता" का अर्थ कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी सेवा को प्रतिफल के लिए किराए पर लेता है या उसका लाभ उठाता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है और "व्यावसायिक उद्देश्य" में उसके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए प्राप्त की गई सेवाएँ शामिल नहीं हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यूटीआई की योजनाओं में भाग लेने की सेवाएँ व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका लाभ विशेष रूप से स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से नहीं लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि विश्वविद्यालय ने अपने फंड के वाणिज्यिक संवर्धन के लिए स्टॉक मार्केट के माध्यम से उच्च रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से यूटीआई की योजना में पैसा निवेश किया था, और यूटीआई द्वारा निवेश पर रिटर्न के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था, इसलिए विश्वविद्यालय को "उपभोक्ता" की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शरण ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय केवल स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय की आजीविका छात्रों को ट्यूशन के रूप में शिक्षा प्रदान करना है। अन्य संबद्ध शुल्क/प्रभार और विश्वविद्यालय की यह गतिविधि 'स्वरोजगार' नहीं है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई

सेवाएँ न तो उनके स्वयं के रोजगार के लिए थीं और न ही उनकी आजीविका के लिए थीं और इसलिए लेनदेन लाभ कमाने और उच्च दर की वापसी के उद्देश्य से शेयर बाजार में निवेश के उद्देश्य से थे और इस प्रकार यह 'व्यावसायिक उद्देश्य' के लिए होगा।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शरण ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि विश्वविद्यालय ने सीपीएफ/जीपीएफ और पेंशन फंड का पैसा निवेश किया और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान भी किया जाता है। इन निवेशों से अर्जित ब्याज से। श्री शरण के अनुसार, उपर्युक्त ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि स्टॉक मार्केट में विश्वविद्यालय द्वारा निवेश मुनाफा कमाने के लिए है और उच्च रिटर्न के लिए ये जोखिम पूरी तरह से वाणिज्यिक उद्यम हैं जिनका स्पष्ट इरादा और मकसद उच्च वाणिज्यिक लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करना है। विश्वविद्यालय ताकि वह पेंशनभोगियों को भुगतान के अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हो सके।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शरण ने आगे कहा कि यह स्वीकार किए बिना भी कि यूटीआई विश्वविद्यालय को सेवाएं प्रदान कर रहा है, सेवाओं में कोई कमी नहीं है जैसा कि विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया है। यह श्री शरण का मामला है कि विश्वविद्यालय ने पुनर्निवेश विकल्प चुना और यूटीआई ने तत्कालीन प्रचलित एनएवी पर आय को आगे की इकाइयों में पुनर्निवेशित कर दिया और योजना के अंत में, यूटीआई ने मूल इकाइयों को ऑफर दस्तावेज़ के संदर्भ में सममूल्य पर भुनाया है। और पुनर्निवेशित इकाइयों को योजना के संदर्भ में प्रचलित एनएवी दर पर भुनाया गया।

14. उपरोक्त के अलावा, श्री शरण ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय आयोग यह समझने में विफल रहा कि आईआईएसएफयूएस-98 में निवेश "व्यावसायिक प्रकृति" का

था क्योंकि इसमें पुनर्निवेश पर प्रति वर्ष 13.5% की दर से उच्च रिटर्न प्रदान किया गया था। अधिक व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और/या ऋण बाजार में व्यावसायिक उद्यम। योजना में किया गया संपूर्ण निवेश उच्च वाणिज्यिक रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से था और इस प्रकार यह पूरी तरह से एक वाणिज्यिक उद्देश्य है।

15. यूटीआई के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि राष्ट्रीय आयोग ने एलएलएसएफयूएस-98 के प्रावधानों को ध्यान में न रखकर गलती की है, लेकिन तथ्य यह है कि निवेश कर्मचारी पेंशन और भविष्य निधि द्वारा उत्पन्न धन से किया जा रहा था और तत्काल विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक विचार के लिए किया गया निवेश,' स्वयं एक व्यावसायिक उद्यम है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकालते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं कि व्यक्तिगत कर्मचारियों द्वारा कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया था और न ही वे उच्च आय के लाभार्थी थे और यह पूरी तरह से एक संस्थागत निवेश था और इस निवेश का लाभार्थी केवल संस्थान था। व्यक्तिगत कर्मचारियों को उनके ईपीएफ और पेंशन अंशदान पर उच्च ब्याज दर का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन वे लागू भविष्य निधि योजना के अनुसार निश्चित ब्याज दर के हकदार होंगे, भले ही धन उनके समर्थन में निवेश किया गया हो या नहीं। तर्कों में, श्री शरण ने मॉर्गन स्टेनली म्यूचुअल फंड बनाम कीर्तिकदास२ और लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

16 योग्यता के आधार पर श्री शरण के व्यापक तर्क यह हैं कि यूटीआई ने उन संस्थागत निवेशकों के लिए पांच साल के लिए एक क्लोज्ड एंडेड एल एलएसएफयूएस-98 की स्थापना की है जो एक विशेष योजना में बड़ी मात्रा में निवेश करना चाहते थे और एल एलएसएफयूएस-98 के अनुसार, दो विकल्प थे निवेशकों के लिए उपलब्ध, पहला विकल्प यह था कि यूटीआई निवेशित राशि पर 13.5% का आश्वासन देता था

और दूसरा विकल्प यह था कि निवेशक के पास 13.5% की दर से आगे की इकाइयों में आय का पुनर्निवेश चुनने का विकल्प था, जिसकी आय निवेशक के खाते में जाएगी। . पंजाब विश्वविद्यालय ने अपनी इच्छा से "पुनर्निवेश विकल्प" का विकल्प चुना था, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र से स्पष्ट है और एलएलएसएफयूएस-98 के "पुनर्निवेश विकल्प" के अनुसार, सभी यूनिट धारकों के पास पुनर्निवेश का विकल्प था। एलएलएसएफयूएस-98 के 'ऑफ़र दस्तावेज़' के खंड XXVII के संदर्भ में एन एवी पर बकाया इकाइयों पर सालाना 13.5% की दर से आगे की इकाइयों में प्राप्त आय, जिसके अनुसार खंड XXVII के तहत पुनर्निवेश विकल्प के तहत आवंटित इकाइयाँ नहीं हैं न्यूनतम होल्डिंग, पुनर्खरीद और अन्य मामलों के संबंध में मूल इकाइयों को नियंत्रित करने वाली शर्तों और शर्तों के अधीन।

खंड XXVII के अनुसार, शिकायतकर्ता सहित सभी यूनिट धारक एलएसएफयूएस-98 के तहत विश्वविद्यालय को योजना के प्रावधानों के अनुसार परिपक्वता राशि का भुगतान किया गया था यानी मूल इकाइयों को गारंटी के बराबर पुनर्खरीद किया गया था और परिपक्वता के समय प्रचलित एनएवी पर पुनर्निवेश विकल्प के माध्यम से अर्जित इकाइयों को जमा किया गया था। योजना के अनुसार टाई विश्वविद्यालय की आय को यूटीआई द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित एनवी में प्रतिवर्ष पुनर्निवेशित किया जाता था। इसके अलावा, यूटीआई के अध्यक्ष द्वारा 9 मार्च 1998 को लिखे गए पत्र में उन्होंने निवेश की गई पूंजी पर प्रति वर्ष 13.5°/से. की वापसी के संबंध में आश्वासन दिया था, और उक्त कूड़े के साथ प्रस्ताव की शर्तें संलग्न की गई थीं, जो कि दी गई थीं। निवेशक को 13.5% प्रति वर्ष की राशि प्राप्त करने का एक विकल्प। यूटीआई इकाइयों को खरीदकर उक्त रिटर्न को फिर से निवेश करने के लिए नकद में; प्रस्ताव की शर्तों में यह भी प्रावधान किया गया है कि आय/रिटर्न के पुनर्निवेश का विकल्प स्थानीय बिक्री के बिना मौजूदा एनएवी पर होगा। श्री शरण ने यह प्रस्तुत

करते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं कि उपरोक्त प्रस्तुतियों के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोग ने गुण-दोष के आधार पर पंजाब विश्वविद्यालय की शिकायत को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

17. संबंधित पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और हमारे सामने प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर करने के बाद, हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में उत्तर दिया जाने वाला प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या शिकायतकर्ता-विश्वविद्यालय "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे में आते हैं जैसा कि स्वयं निर्धारित है। अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में और यह कि उनके द्वारा प्रदान की गई "सेवाएं" किसी "व्यावसायिक उद्देश्य" के लिए नहीं हैं। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के आधार पर हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या विद्वान आयोग ने योग्यता के आधार पर शिकायत को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

18. हमने देखा कि धारा 2(1)(डी) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण में, 2003 में एक संशोधन के माध्यम से (15 मार्च 2003 से) शब्द "उप-खंड (i)" को और अधिक व्यापक बनाने के लिए "खंड" के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। व्याख्यात्मक उपवाक्य की योग्यता का दायरा। संशोधनों के आलोक में जो दुविधा मौजूद है वह यह है कि क्या शिकायतकर्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं (यूटीआई के माध्यम से किए गए आईआईएसएफयूएस-98 में निवेश के रूप में) उन्हें "व्यावसायिक उद्देश्य" के लिए उपयोग की जा रही सेवाओं के आधार पर अधिनियम के तहत उपभोक्ता होने से रोकती हैं। ". इसे निर्धारित करने के लिए हम "व्यावसायिक उद्देश्य" शब्द की विभिन्न व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे।

19. लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स (सुप्रा) में जीआईएस कोर्ट ने "वाणिज्यिक उद्देश्य" वीज़ा शब्द के अर्थ को "उपभोक्ता" की परिभाषा के साथ सबसे विस्तृत रूप से निपटाया

है और स्थिति आज तक वही बनी हुई है। हम उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग का उल्लेख इस प्रकार करेंगे:

"अब धारा 2(डी) में अभिव्यक्ति 'उपभोक्ता' की परिभाषा पर वापस आते हुए, एक उपभोक्ता का मतलब है जहां तक इस अपील के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, (i) एक व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए कोई सामान खरीदता है; यह है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिफल का भुगतान किया गया है या वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या क्या प्रतिफल का भुगतान स्थगित कर दिया गया है; (ii) एक व्यक्ति जो ऐसे सामान का उपयोग उस व्यक्ति की मंजूरी से करता है जो ऐसे सामान को प्रतिफल के लिए खरीदता है (iii) लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसे सामान को पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदता है। अभिव्यक्ति "पुनर्विक्रय" काफी स्पष्ट है, तथापि, "व्यावसायिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के अर्थ के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है। इसे अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषा के अभाव में हमें इसके सामान्य अर्थ से ही चलना पड़ता है। "वाणिज्यिक" का अर्थ "वाणिज्य से संबंधित" है (चैम्बर्स ट्वेंटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी); इसका अर्थ है "वाणिज्य से जुड़ा हुआ या उसमें लगा हुआ; व्यापारिक; मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ प्राप्त करना" (कोलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश? जबकि "वाणिज्य" शब्द का अर्थ है "वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर माल की खरीद और बिक्री" (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी)).ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आयोग लगातार यह विचार कर रहा है कि जहां कोई व्यक्ति "लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि को चलाने के लिए ऐसे सामान का उपयोग करने की दृष्टि से" सामान खरीदता है, तो वह "उपभोक्ता" नहीं होगा। "अधिनियम की धारा 2(डी)(आई) के अर्थ के भीतर। मोटे तौर पर उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि करना और विशेष रूप से किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर

अभिव्यक्ति" बहुत सटीक अभिव्यक्ति नहीं है जिसे संसद ने हस्तक्षेप किया और जोड़ा अध्यादेश/संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा धारा 2(डी)(i) की व्याख्या। स्पष्टीकरण अपवाद के मामले में "व्यावसायिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के दायरे से कुछ उद्देश्यों को बाहर करता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त निर्णय में यह न्यायालय 'माल की बिक्री' से निपट रहा था, हालांकि, बेंच ने अपने सभी विवेक से यह स्पष्ट कर दिया कि 1993 के संशोधन के बाद, 'व्यावसायिक उद्देश्य' क्या है, यह 'तथ्यों' द्वारा शासित होगा प्रत्येक मामले का'. इस न्यायालय ने आगे कहा कि संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया स्पष्टीकरण प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण है और चूंकि अधिनियम का मतलब हमेशा एक ही होता है, इसलिए संशोधन सभी लंबित कार्यवाहियों पर भी लागू होगा।

20. लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स (सुप्रा) में यह न्यायालय लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के.गुप्ता३ में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा करते हुए, निम्नानुसार देखा गया: -

> "लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता मामले में सवाल यह था कि क्या मकान बनाने और बेचने में लगे एक सार्वजनिक प्राधिकरण को 'सेवा' प्रदान करने वाला कहा जा सकता है और क्या ऐसे मकान खरीदने वाले व्यक्ति को उक्त के अर्थ में 'उपभोक्ता' कहा जा सकता है परिभाषा। प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ (कुलदीप सिंह और आर. एम. सहाय) ने अधिनियम की योजना और उद्देश्य और अभिव्यक्ति 'उपभोक्ता' की परिभाषा के दायरे की भी जांच की। निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं उपयुक्त :(एससीसी पृ. 251-54, पैरा 2 और 3)

अधिनियम की प्रस्तावना से शुरू करने के लिए, जो विधायी इरादे को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी सहायता प्रदान कर सकता है, इसे 'उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए' अधिनियमित किया गया था। 'संरक्षण' शब्द का उपयोग दिमाग में कुंजी प्रस्तुत करता है अधिनियम के निर्माताओं की। विभिन्न परिभाषाएँ और प्रावधान जो विस्तृत रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें स्थापित दृष्टिकोण से विचलित हुए बिना इस प्रकाश में समझा जाना चाहिए कि एक प्रस्तावना किसी प्रावधान के अन्यथा स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकती है। वास्तव में कानून लंबे समय से महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करता है आम आदमी को ऐसी गलतियों से बचाना जिनके लिए विभिन्न कारणों से सामान्य कानून के तहत उपचार भ्रामक हो गया है।

Xxx xxx xxx

'उपभोक्ता' शब्द एक व्यापक अभिव्यक्ति है। इसका विस्तार उस व्यक्ति से है जो किसी दुकान, व्यापारिक घराने, निगम, स्टोर, उचित मूल्य की दुकान से खाने योग्य या अन्यथा उपभोग करने के लिए कोई वस्तु खरीदता है और निजी या सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उपभोक्ता को 'वस्तुओं या सेवाओं का खरीदार' के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसका अर्थ 'उपभोग करने वाला' बताया गया है। वे व्यक्ति जो उत्पादों और सेवाओं की खरीद, उपयोग, रखरखाव और निपटान करते हैं।

लोगों के उस व्यापक वर्ग का सदस्य जो मूल्य निर्धारण नीतियों, वित्तपोषण प्रथाओं, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, क्रेडिट रिपोर्टिंग, ऋण वसूली और अन्य व्यापार प्रथाओं से प्रभावित होते हैं जिनके लिए राज्य और संघीय उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाए जाते हैं। अधिनियम किसी कम व्यापक परिभाषा का विकल्प नहीं चुनता है।

Xxx xxx xxx

यह दो भागों में है. पहला वस्तुओं से संबंधित है और दूसरा सेवाओं से संबंधित है। दोनों भाग पहले व्यापक अभिव्यक्तियों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के अर्थ की घोषणा करते हैं। समावेशी उपवाक्य के प्रयोग से उनका दायरा और भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यह न केवल वस्तुओं का खरीदार या सेवाओं को किराए पर लेने वाला है, बल्कि वे भी हैं जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं या जो लाभार्थी हैं। इसमें उस व्यक्ति की मंजूरी से सेवाएं शामिल हैं जिसने सामान खरीदा है या जिसने सेवाएं किराए पर ली हैं। विधायिका ने न केवल 'शिकायत', 'शिकायतकर्ता', 'उपभोक्ता' को परिभाषित करने के लिए सावधानी बरती है, बल्कि खंड ® में एक विस्तृत परिभाषा देकर और यहां तक कि 'दोष' और 'को परिभाषित करने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार की राशि क्या होगी, इसका भी विस्तार से उल्लेख किया है। 'कमी' वर्ग (एफ) और (जी) द्वारा जिसके लिए उपभोक्ता आयोग से संपर्क कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता के आर्थिक हितों की रक्षा करना है, जैसा कि वाणिज्यिक अर्थ में माल के

खरीदार के रूप में और सेवाओं के उपयोगकर्ता के बड़े अर्थ में समझा जाता है।"

उपरोक्त उद्धरणों से यह देखा जा सकता है कि धारा 2(1)(डी)(i) पर इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से चर्चा की गई है। हम। हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के खंड, (i) और (ii) की सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्याख्या की जानी चाहिए और उसी के प्रकाश में, हम पाते हैं कि धारा 2(1 }(डी) के बाद स्पष्टीकरण (ii) अधिनियम प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण होगा और वर्तमान मामले पर लागू होगा और जैसा कि लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, शब्द "व्यावसायिक उद्देश्य" की व्याख्या प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए की जानी चाहिए।

21. यूनाइटेड किंगडम के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 की धारा 20(6) के तहत, "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा इस प्रकार है:

"उपभोक्ता- (ए) किसी भी सामान के संबंध में कोई भी व्यक्ति जो अपने निजी उपयोग या उपभोग के लिए सामान की आपूर्ति करना चाहता है,

(बी) किसी भी सेवा या सुविधा के संबंध में, इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी व्यवसाय के प्रयोजनों के अलावा अन्यथा सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करना चाहता है और

(सी) किसी भी आवास के संबंध में, इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी व्यवसाय के प्रयोजनों के अलावा अन्यथा आवास पर कब्जा करना चाहता हो;"

स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश के अनुसार "वाणिज्यिक" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"वाणिज्यिक- (1) वाणिज्यिक कार्रवाई में व्यापारियों और व्यापारियों के सामान्य लेनदेन से उत्पन्न होने वाला कोई भी खंड शामिल है और, पूर्वगामी शब्दों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यापारिक दस्तावेज़ के निर्माण, माल के निर्यात या आयात से संबंधित कोई भी कारण, माल ढुलाई, बीमा, बैंकिंग, व्यापारिक एजेंसी और व्यापारिक उपयोग

(2) एक निगमित नहर कंपनी जिसका मुनाफा टोल से होता था, उसे एक 'वाणिज्यिक कंपनी' या "वाणिज्यिक उद्देश्यों" के लिए संबद्ध कंपनी माना गया और, इस तरह, संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम 1844 के तहत दिवालिया होने के लिए उत्तरदायी थी।

इस प्रकार, 'व्यावसायिक उद्देश्य' शब्द एक ऐसे उपक्रम को कवर करेगा जिसका उद्देश्य उपक्रम से लाभ कमाना है। वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता द्वारा अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए यूटीआई की सेवाओं का लाभ उठाया गया था, इस तरह का निवेश किया गया था, और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि लाभ के रूप में शिकायतकर्ता को कोई लाभ नहीं मिलना था, इसमें सुधार हुआ बैलेंस शीट में, ऊपर दी गई 'वाणिज्य' शब्द की परिभाषा के मद्देनजर, किसी भी परिस्थिति में, अपीलकर्ता को किसी भी 'वाणिज्यिक' गतिविधि में शामिल नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार उसे अधिनियम में निहित 'उपभोक्ता' की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है। वर्तमान विवाद में विश्वविद्यालयों का इरादा मुनाफाखोरी का नहीं है और यह परोपकारी हित के लिए है और इसका कोई इरादा नहीं है कि निवेश किसी व्यावसायिक उद्देश्य या लाभ के लिए किया गया है और इसलिए हम पाते हैं कि शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय "उपभोक्ता" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम के तहत और शिकायतें राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विचारणीय हैं।

22. अब, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या ऑफर के संदर्भ में सेवाओं में कोई कमी है। इस संबंध में राष्ट्रीय आयोग के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

'प्रस्ताव की शर्तें विशेष रूप से प्रदान करती हैं कि यूटीआई 13.5% प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करेगा। योजना के सभी 5 वर्षों के लिए। पहले वर्ष के लिए उक्त रिटर्न (आय) का भुगतान जुलाई, 1998 में करने पर सहमति हुई थी। इसके बाद, बाद के वर्षों के लिए आय का भुगतान प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाना था। 1 जुलाई 2002 से 31 मई 2003 तक की शेष अवधि की आय का भुगतान मई 2003 में किया जाना था। इसके बाद निवेशकों को मौजूदा एनएवी के अनुसार आय को दोबारा निवेश करने का विकल्प दिया गया। परिपक्वता पर यह गारंटी दी जाती है कि पुनर्खरीद मूल्य इकाइयों के सममूल्य यानी 10/- रुपये से कम नहीं होगा। हालाँकि, समय से पहले पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है और खरीद मूल्य एनएवी पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, योजना के तहत सुनिश्चित आय और परिपक्वता पर पूंजी की सुरक्षा की गारंटी ट्रस्ट के विकास रिजर्व फंड द्वारा दी जाती है।

निवेश की गई पूंजी के संबंध में, माना जाता है कि इकाइयों को यूनिट के सममूल्य पर यानी 10 रुपये पर पुनर्खरीद किया जाता है, एनएवी पर नहीं।

सके बाद, नियम और शर्तें प्रस्ताव दस्तावेज़ में प्रदान की जाती हैं। मुख्य आकर्षणों में से एक यह प्रदान करता है कि योजना में निवेश की गई पूंजी परिपक्वता पर संरक्षित की जाएगी और इकाइयों को भुनाया नहीं जाएगा।

हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि रिटर्न/लाभांश से खरीदी गई इकाइयों के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यह सत्य है कि इस शब्द में अस्पष्टता है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या उक्त शब्द इकाइयों की समयपूर्व पुनर्खरीद पर लागू होता है या वार्षिक रिटर्न, यानी लाभांश से खरीदी गई इकाइयों की पुनर्खरीद पर लागू होता है। हालाँकि, इसे पैरा-एक्स के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो इकाइयों की पुनर्खरीद की विधि प्रदान करता है। इसमें भी वही पदावली प्रयुक्त होती है जो ऊपर कही गयी है।

हालाँकि, खंड यह स्पष्ट करता है कि 13.5% प्रति वर्ष की दर से रिटर्न या लाभांश को एनएवी के आधार पर पुनर्निवेश किया जाना है, इसका मतलब है कि, यदि इकाई की कीमत 9/- रुपये है, तो आय इकाइयों में निवेश की जाएगी और प्रत्येक इकाई के लिए खरीद मूल्य रु.9/- होगा, भले ही इसका अंकित मूल्य रु.10/- हो।

इसके बाद, पैरा XXVII आगे की इकाइयों में वितरित की जाने वाली आय के पुनर्निवेश का प्रावधान करता है। यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि: "एक इकाई धारक जिसने पुनर्निवेशित इकाइयों को पुनर्खरीद किया है, वह बाद के वर्षों के लिए वितरित आय के संबंध में पुनर्निवेश सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकता है। इस खंड के तहत पुनर्निवेश सुविधा के तहत आवंटित इकाइयां शर्तों के अधीन नहीं हैं और न्यूनतम होल्डिंग, पुनर्खरीद के संबंध में मूल इकाइयों को नियंत्रित करने वाली शर्तें अन्य मामले हैं।"

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में इस पर विचार किया है और हमने पाया है कि गुण-दोष के आधार पर, शिकायतकर्ताओं के पास कोई मामला नहीं है। प्रस्ताव की शर्तों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि परिपक्वता राशि एनएवी पर निर्भर करेगी और यह गारंटी दी गई थी कि यह रुपये के सममूल्य से कम नहीं होगी। 10 प्रति यूनिट. सभी निवेश बाजार के जोखिमों और उतार-चढ़ाव के अधीन हैं और एक निवेशक को किसी भी योजना में कोई भी राशि निवेश करते समय उचित सावधानी बरतनी होती है, सिर्फ इसलिए कि परिपक्वता राशि उनकी अपेक्षाओं से कम है, वे इसके लिए सेवा प्रदाता को अदालत में नहीं खींच सकते।

23. पिछले पैराग्राफ में बताए गए कारणों और हमारी चर्चा के आधार पर, हम मानते हैं कि राष्ट्रीय आयोग ने सही ढंग से कहा कि विश्वविद्यालय "उपभोक्ता" के दायरे

में आएगा जैसा कि उक्त धारा 2(1)(डी) में परिभाषित है। कार्रवाई की और गुण-दोष के आधार पर शिकायतकर्ताओं के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया।

24. उपरोक्त चर्चा के आलोक में 2007 की सिविल अपील संख्या 400 में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज कर दिया गया है। 2008 की सिविल अपील संख्या 503 और 2009 की 4664 का निपटारा इस निर्णय के अनुसार किया जाता है।

राजेंद्र प्रसाद

अपील निस्तारित की जाती है।

---

१ (1995) 3 एस सी सी 583

२ (1994) एस सी सी 225

३ (1994) 1 एस सी सी 225

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।